

विद्युत् गतिशीलता की लम्बी राह



लेख में सरकार के नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जिसके माध्यम से देश को 100% इलेक्ट्रिक वाहन उपयोग में लाने वाले राष्ट्र में विकसित करने के विषय पर चर्चा की गई है।

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएमपी) देश में मोटर वाहन और परिवहन परिदृश्य में बदलाव लाने की दिशा में सरकार की एक सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है।
- इसके अंतर्गत एक व्यापक योजना की परिकल्पना की गई है, जिसमें बिजली को गतिशीलता प्रदान करने के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
 1. हाइब्रिड या बिजली के वाहनों को प्रोत्साहन;
 2. बैटरी प्रौद्योगिकी, के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना जिसमें बैटरी प्रबंधन, प्रणाली एकीकरण, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोटर्स, आदि के क्षेत्रों का विकास करना शामिल है;
 3. पावर और चार्जिंग से सम्बंधित बुनियादी ढांचे को विकसित करना;
 4. आपूर्ति पक्ष प्रबंधन;
 5. पुराने वाहनों की हाइब्रिड किट लगा कर रेट्रोफिटिंग को प्रोत्साहन देना।
- एनईएमएमपी के तहत देश भर में 2020 तक 6-7 लाख यूनिट वाहनों को बनाने की परिकल्पना की गई थी जिससे भारत दुनिया राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा की दिशा में योगदान करने वाले देशों की अग्र श्रेणी में आ सके।
- सरकार अब इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना बना रही है जिसका उद्देश्य 2030 तक भारत को एक 100% इलेक्ट्रिक वाहन राष्ट्र के रूप में विकसित करना है।
- भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग ने पिछले एक दशक में जबरदस्त प्रगति की है और भारत दुनिया में छठा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता देश के रूप में बन कर उभरा है।
- मध्यम वर्ग की आबादी, की वृद्धि को देखते हुए भविष्य में शहरीकरण और अपर्याप्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे तथा वाहनों के उपयोग को भी बढ़ने की संभावना है।

- हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि वाहनों का उपयोग न केवल विकसित देशों की तुलना में, लेकिन कुछ विकासशील देशों जैसे चीन, मलेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका से भी कम होना चाहिए।
- इसलिए, यह वर्ष 2030 तक 100% बिजली के वाहनों को गतिशीलता प्रदान करना एक विशाल कार्य है।
- वाहनों के लिए बिजली और उनके चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचे का विकास और उसका प्रबंधन बिजली के वाहनों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक है।
- इस तरह के वाहनों की सफलता चार्जिंग के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं के विकास और उनकी सुगम एवं सस्ती कीमत की उपलब्धता पर से जुड़ा हुआ है।
- ऐसे वाहनों का विकास निजी और सार्वजनिक चार्ज स्टेशनों मौजूदगी पर भी निर्भर करेगा जिसके लिए निम्न और मध्यम वोल्टेज बिजली नेटवर्क को एकीकृत किये जाने की भी आवश्यकता होगी।
- इसके लिए विभिन्न हितधारकों-दोनों विनियमित और गैर विनियमित के बीच सहयोग की व्यापक आवश्यकता होगी।
- बिजली की गतिशीलता पहल और अक्षय ऊर्जा स्रोतों एक एकीकृत रूप में विकसित किया जाना चाहिए जिससे स्वच्छ वातावरण, बिजली की आपूर्ति की गुणवत्ता, और कुशल पारेषण और वितरण की सुविधा आदि सुनिश्चित की जा सके।
- बिजली के वाहनों की बैटरी ऊर्जा की परिवर्तनशीलता के बीच संतुलन साधने के लिए आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है।
- यह संभव है कि बिजली की गतिशीलता स्मार्ट ग्रिड विकास का एक अभिन्न हिस्सा हो सकती है।
- इस तरह के एक बहुत मजबूत आईसीटी ढांचे का विकास करने के लिए एक बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।
- बिजली की गतिशीलता सेवाओं को प्रसारित करने के लिए एक बड़ी संख्या में हितधारकों की आवश्यकता है और उनकी भूमिकाओं को भी परिभाषित किए जाने की जरूरत है।
- हमें इससे सम्बंधित अपने देश के लिए सबसे अच्छा मॉडल विकसित करने के लिए इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, नई तकनीक, बड़े पैमाने पर निवेश, त्वरित कार्यान्वयन और अर्थव्यवस्था को इसके अनुकूल विकसित करने की आवश्यकता है।
- बाजार सहभागियों उचित नियमों, प्रारंभिक सब्सिडी और योजना स्थापित करने के लिए पर्याप्त समय व्यापार की प्रधानता की आवश्यकता है।

प्रश्न:

देश में मोटर वाहन और परिवहन परिदृश्य में बदलाव लाने की दिशा में राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 (एनईएमएपी) सरकार की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी पहल है। चर्चा कीजिये।

सुझाव बिंदु:

1. एनईएमएपी की विशेषताएं।
 2. इससे समाज कैसे लाभ होगा।
 3. सीमाओं जिनको दूर किये जाने की आवश्यकता है।
-

लिंक : <http://www.financialexpress.com/fe-columnist/long-way-to-go-for-electric-mobility/352405/>

संकलन : मनीष कुमार सिंह



CHANAKYA
IAS ACADEMY

Nurturing Leaders of Tomorrow